जनसत्ता

वायुसेना की ताकत

अपने साढ़े आठ दशक से ज्यादा के सफर में भारत की वायुसेना ने जितने पड़ाव देखे हैं, वे उसकी सफल विकास यात्रा को बयान करते हैं। भारत को चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध भी लड़ने पड़े और वायुसेना ने जिस शौर्य और सजगता के साथ दुश्मन देश के छक्के छुड़ाए, उसे कैसे भुलाया जा सकता है! आज भारत के लिए गौरव की बात है कि उसकी वायुसेना दुनिया की चौथी बड़ी और सर्वश्रेष्ठ वायुसेना में गिनी जाती है। मंगलवार को वायुसेना दिवस के मौके पर वायुसेना के इतिहास में उस वक्त एक नया अध्याय और जुड़ जाएगा जब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस के बारडेक्स शहर में पहला रफाल विमान हासिल करेंगे। रफाल विमान वायुसेना की ताकत में और इजाफा करेगा। भारत की वायुसेना को लंबे समय से उन्नत विमानों की जरूरत थी। रफाल विमानों की खूबी यह है कि ये विमान हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर और स्काल्प मिसाइलों से लैस हैं। इसके अलावा रफाल को वायुसेना ने अपनी जरूरतों के हिसाब से तैयार करवाया है। अभी भारत के लड़ाकू विमानों के बेड़े में सुखोई, मिग-21 बायसन और जगुआर जैसे विमान मोर्चा संभालते हैं।

भारत को आज अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान और चीन से जिस तरह की सामरिक चुनौतियां मिल रही हैं और एशियाई क्षेत्र में जैसा शक्ति संतुलन बन रहा है, उसे देखते हुए वायुसेना का आधुनिकीकरण अपरिहार्य हो गया है। आज तकनीक का जमाना है और युद्ध के तौर-तरीके भी बदल चुके हैं। सेकेंडों में दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने वाले हथियार और विमान वायुसेना की जरूरत बन चुके हैं। कुछ समय पहले ही भारत की वायुसेना में दुनिया के अत्याधुनिक लड़ाकू हेलिकॉप्टर- अपाचे एएच-64ई को शामिल किया गया था। ये हेलिकॉप्टर अमेरिका से खरीदे गए थे। अभी भारत के पास आठ अपाचे हेलिकॉप्टर हैं। इनके अभाव में वायुसेना को इन हेलिकॉप्टरों की जरूरत कई सालों से थी। अपाचे की मदद से पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर घुसपैठियों को ढेर किया जा सकेगा। ये विमान अंधेरे में भी लक्ष्य को भेद सकते हैं। ऐसे में अपाचे सीमा की सुरक्षा में ज्यादा कारगर साबित होंगे। इसके अलावा ऊंचे और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में सैनिकों को लाने-ले जाने, रसद और हथियार पहुंचाना वायुसेना के लिए अब तक मुश्किलों भरा काम साबित हो रहा था। इसके लिए चिनूक हेलिकप्टर खरीदे गए थे। कुल मिला कर देखा जाए तो भारत ने वायुसेना को नए से नए विमानों और हेलिकॉप्टरों से सुसज्जित करने की दिशा में काफी काम किया है।

हालांकि पुराने विमानों से पीछा अभी पूरी तरह छूट नहीं पाया है। भारत के पास अभी भी बड़ी संख्या में मिग विमान हैं। रूस से खरीदे गए इन विमानों का जीवनकाल एक तरह से पूरा हो चुका है। एक तरह से घिसे-पिटे विमानों की श्रेणी में ही आते हैं, लेकिन इन्हें समय-समय पर उन्नत बना कर काम निकाला जाता रहा। जब तक नए विमानों की खेप नहीं मिल जाती, मिग विमानों पर निर्भरता बने रहना वायुसेना की मजबूरी है। मिग विमानों के बढ़ते हादसे वायुसेना के लिए गंभीर चिंता का विषय रहे हैं। सैंकड़ों जाबांज पायलट शहीद हुए हैं। इसका बड़ा कारण यह रहा कि वायुसेना का आधुनिकीकरण सरकार की प्राथमिकता में नहीं रहा और इसी वजह से अत्याधुनिक विमानों की खरीद प्रक्रिया में जरूरत से ज्यादा विलंब होता चला गया। लेकिन अब लग रहा है कि वक्त बदला है और सेना की जरूरतों पर ध्यान गया है। सैन्य क्षमता को बढ़ाना और उन्नत करना राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जरूरी है।

शिक्षा की सूरत

किसी भी देश में विकास की असली कसौटी यह होनी चाहिए कि वहां शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की तस्वीर कैसी है। ये तीनों क्षेत्र परस्पर जुड़े हुए हैं, इसलिए एक के बेहतर या कमतर होने का असर सीधे तौर पर दूसरे पर पड़ता है। जहां तक भारत में सरकारी व्यवस्था के तहत उपलब्ध कराई जाने वाली शिक्षा का सवाल है तो लंबे समय से इस क्षेत्र में अलग-अलग पहलू से सुधार के सवाल उठाए जाते रहे हैं। खासतौर पर शिक्षकों की कमी का मसला पिछले कई दशकों से लगातार चिंताजनक स्तर पर कायम है, लेकिन दूसरे तमाम क्षेत्रों में विकास के दावों के बरक्स यह हकीकत है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए संतोषजनक कदम भी नहीं उठाए गए। इसमें भी एक बड़ा पहलू अब यह उभर कर सामने आया है कि देश भर में बहुत बड़ी तादाद ऐसे सरकारी स्कूलों की है जो बिना किसी प्रधानाध्यापक के संचालित हो रहे हैं। सवाल है कि शिक्षकों की कमी से जूझते स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के अभाव के बीच पढ़ाई-लिखाई की कैसी तस्वीर बन रही होगी?

गौरतलब है कि नीति आयोग की ओर से जारी पहले विद्यालय शिक्षा गुणवत्ता सूचक के मुताबिक अलग-अलग राज्यों में ऐसे हजारों स्कूल हैं जहां कोई प्रधानाध्यापक नहीं है। सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति में बिहार है, जहां के करीब अस्सी फीसद स्कूल बिना प्रधानाध्यापक के चल रहे हैं। हालत यह है कि राजधानी दिल्ली तक में करीब एक तिहाई विद्यालय ही प्रधानाध्यापक के साथ चल रहे हैं। गुजरात, केरल, तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों की तस्वीर जरूर संतोषजनक है, लेकिन देश के ज्यादातर राज्यों में अगर चालीस, पचास या अस्सी फीसद स्कूलों में प्रधानाध्यापक नहीं हैं, तो समझा जा सकता है कि सरकारें स्कूली शिक्षा में सुधार के प्रति किस हद तक उदासीन हैं। नीति आयोग के ताजा आंकड़े को तैयार करने में खुद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्व बैंक ने भी सहयोग किया है। ये आंकड़े सन 2016-17 के हैं, लेकिन आज भी इस तस्वीर में कोई खास बदलाव नहीं आया है। हाल में आई एक खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के शिक्षक संगठनों ने यह आरोप लगाया कि राज्य में एक लाख से ज्यादा प्रधानाध्यापकों के पद ही समाप्त कर दिए हैं! क्या सरकारों को लगता है कि शिक्षकों की कमी की गंभीर समस्या को दूर करने के बजाय प्रधानाध्यापकों की जगह भी खत्म या कम करके शिक्षा की सूरत में बदलाव लाया जा सकता है?

इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि एक ओर देश में सरकारें शिक्षा का अधिकार कानून लागू करके और व्यापक स्तर पर शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभियान चला कर पढ़ाई-लिखाई की सूरत को चमकाने का दावा करती हैं, लेकिन इस तकाजे पर उन्हें यह गौर करना जरूरी नहीं लगता कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के मुताबिक सभी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में एक प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक और उपप्रधानाचार्य या फिर सहायक प्रधान अध्यापक नियुक्त करना अनिवार्य है। सवाल है कि जब स्कूलों में प्रधानाध्यापकों की मौजूदगी के मामले में यह अफसोसजनक तस्वीर है तो देश भर में लाखों की तादाद में शिक्षकों की कमी का मुद्दा सरकार की प्राथमिकता में कहां होगा! ऐसे में गुणवत्ता से लैस शिक्षा मुहैया कराना तो दूर, अंदाजा लगाया जा सकता है कि सामान्य औपचारिक पढ़ाई-लिखाई भी किस दशा में चल रही होगी। अगर इस सूरत में जल्दी सुधार लाने और स्कूलों में जरूरत के मुताबिक पूरे शिक्षक मुहैया करा कर गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई-लिखाई सुनिश्चित नहीं की गई तो देश के कमजोर आर्थिक हैसियत वाले तबकों के बच्चे शिक्षा के दायरे से बाहर हो जाएंगे या फिर उनके साक्षर होने का कोई मतलब नहीं होगा!

कल्पमेधा

पराधीनता समाज के मौलिक
नियमों के विरुद्ध है।
- मांटेस्क्यू

बेरोजगारी का गहराता संकट

अभिषेक कुमार सिंह

भारत में 2018 में बेरोजगारी की दर पांच फीसद थी, लेकिन इसमें भी पंद्रह से उनतीस साल के युवाओं में बेरोजगारी तीन गुना ज्यादा यानी पंद्रह फीसद तक थी। इस आयु वर्ग में बेरोजगारी की समस्या शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक थी। बेरोजगारी की इस हालत पर अहम सवाल यह उठता है कि सत्ता और राजनीतिक दलों के लिए बेरोजगारी अहम चिंता का विषय क्यों नहीं है।

दुनिया की कोई भी सरकार जिन कुछ मोर्चों पर अपनी नाकामी को आसानी से नहीं स्वीकार करती है, उनमें भूख से होने वाली मौतें और बेरोजगारी जैसे मुद्दे प्रमुख होते हैं। हालांकि, इधर देश के रोजगार क्षेत्र में युवाओं की दक्षता और कौशल को लेकर कुछ सवाल उठे हैं और रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है, इसे लेकर भी एक मत बना है, लेकिन इसके बावजूद कुछ सच झुठलाए नहीं जा सकते। जैसे, एक सच यह है कि नोटबंदी के बाद से लाखों लोगों का रोजगार छिन गया और दूसरा यह कि नई नौकरियों के बनने की रफ्तार मंद पड़ गई, जिससे बेरोजगारी आसमान पर पहुंच गई है।

भारत में फिलहाल बेरोजगारी का स्तर क्या है, इसका खुलासा कुछ अध्ययनों और सर्वेक्षणों से हुआ है। जैसे, इस साल जून में प्रकाश में आई नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (एनएसएसओ) की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि वर्ष 2011-12 में बेरोजगारी की जो दर 2.2 फीसद पर थी, वह 2017-18 में बढ़ कर 6.1 फीसद के रिकॉर्ड स्तर पर चली गई। हालांकि इस बढ़ोत्तरी के पीछे एनएसएसओ का कहना था कि बेरोजगारी दर बढ़ने की एक वजह गणना के तरीके का बदला जाना है, जिसमें शिक्षित लोगों को ज्यादा अहमियत दी गई थी। असल में, शिक्षित बेरोजगारी दर निरक्षरों के मुकाबले में हमेशा ज्यादा रहती है, लिहाजा उनके आंकड़ों में बढ़ोत्तरी हो गई। लेकिन बेरोजगारी में वृद्धि का आकलन अकेले एनएसएसओ का नहीं है, बल्कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआइई) ने बीते दो वर्षों के दौरान किए गए सर्वेक्षणों में भी बेरोजगारी की दर में इजाफे को दर्ज किया। सीएमआइई के सर्वे के मुताबिक इस साल अप्रैल 2019 में देश में बेरोजगारी की दर सात फीसद थी। कुछ इसी किस्म के आकलन 'स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2018' में भी पेश किए गए हैं। इस अध्ययन के अनुसार भारत में 2018 में बेरोजगारी की दर पांच फीसद थी, लेकिन इसमें भी पंद्रह से उनतीस साल के युवाओं में बेरोजगारी तीन गुना ज्यादा यानी पंद्रह फीसद तक थी। इस आयु वर्ग में बेरोजगारी की समस्या शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक थी। बेरोजगारी की इस हालत पर अहम सवाल यह उठता है कि सत्ता और राजनीतिक दलों के लिए बेरोजगारी अहम चिंता का विषय क्यों नहीं है।

हो सकता है कि बेरोजगार की श्रेणी में दर्ज किए गए ज्यादातर नौजवान शिक्षित हों, अपने मन की बेहतर नौकरी तलाश कर रहे हों। ऐसे लोगों को बेरोजगार रहते हुए नौकरी की खोज करने का मामला अच्छी नौकरी में किया गया निवेश प्रतीत होता है और वे इसके लिए सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेदार नहीं मानते। अलबत्ता सरकारी नौकरियों में कटौती होना उनके लिए भी चिंता का विषय है। एक दिलचस्प आकलन यह भी कहता है कि औपचारिक क्षेत्र में नौकरियों की संख्या घटने की बजाय असल में बढ़ गई हैं, जिसका खुलासा ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आंकड़ों से होता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) ने दावा किया है कि रोजगार के औपचारिक क्षेत्र में 2018-19 में नौकरियों के एक करोड़ सैंतीस लाख अवसर पैदा हुए। हालांकि इन सारे दस्तावेजी आंकड़ों से यह निष्कर्ष अवश्य निकल रहा है कि अच्छी और सरकारी नौकरियों पर उन नौजवानों का कब्जा होता चला रहा है जिन्होंने किसी तरह ठीक-ठाक डिग्री और कौशल प्रशिक्षण हासिल किया होगा। इस दायरे से बाहर के बेरोजगार नौजवानों के लिए या तो कोई भी नौकरी कर लेने का विकल्प बचता है या फिर हमेशा के लिए बेरोजगार रह जाने का, लेकिन ऐसे लोग कोई आवाज उठाने की हैसियत में नहीं होते। इन संकेतों वाले सारे नतीजों का सार इस साल मार्च में बहुराष्ट्रीय मार्केट रिसर्च कंपनी इप्सॉस के सर्वेक्षण से मिला था। इस सर्वेक्षण में रोजगार को लेकर विभिन्न देशों की जनता की अलग-अलग चिंताएं सामने आई थीं। सर्वे के मुताबिक भारत में ज्यादातर लोगों ने यह माना कि रोजगार सहित कई अन्य मामलों में सरकार की नीतियां सही दिशा में हैं, लेकिन आतंकवाद की चिंता उन्हें सबसे ज्यादा सता रही थी। यह जरूर है कि सर्वेक्षण में शामिल महत्त्वपूर्ण अट्ठाईस देशों के औसतन अट्ठावन फीसद नागरिकों ने माना था कि उनका देश नीतियों के मामले में भटक-सा गया है। लेकिन ऐसा सोचने वालों में भारत की बजाय दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, फ्रांस, तुर्की और बेल्जियम के लोग

ज्यादा थे। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में रोजगार की फिक्र हाशिये पर चली गई है, बल्कि इसमें स्थिति यह बनी है कि इसकी चिंता ग्रामीण के मुकाबले शहरी और अनपढ़ों के मुकाबले शिक्षित नौजवानों को ज्यादा है और इत्तफाक से ऐसे लोगों का भरोसा सरकार की नीतियों पर ज्यादा बना हुआ है, इसलिए इस समस्या को लेकर कोई बड़ा बवाल नहीं उठ रहा है।

हालांकि इस पूरे प्रकरण में जो चिंता सरकारों और उद्योगों की है, वह अलग तरह की है। कहा जा रहा है कि हमारे शिक्षित बेरोजगारों की सबसे बड़ी समस्या उनका उद्योगों के अनुरूप तैयार नहीं होना है। यानी प्रशिक्षण के बावजूद उनमें वह अपेक्षित कौशल नहीं है जो उन्हें रोजगार के काबिल बनाता है। इस कारण बाजार में मौके होने के बावजूद लाखों पद खाली हैं और कंपनियां वांछित योग्य नौजवानों की तलाश में उन्हें भरने में हिचकिचा रही हैं, क्योंकि वैश्विक मंदी के कारण वे ऐसे लोगों को नौकरी देने का जोखिम सहन नहीं कर सकतीं जो नौकरी करते हुए अपने भीतर अपेक्षित कौशल का विकास करते हैं।

ऐसे वक्त में, जब देश में 'स्किल इंडिया' जैसे महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम में 2022 तक देश के चालीस करोड़ युवाओं को हुनरमंद बना कर उन्हें रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, सर्वेक्षणों के ऐसे आंकड़े हैरान करते हैं। ऐसी स्थिति में अहम सवाल यह पैदा होता है कि अगले कुछ वर्षों में आखिर देश कैसे यह इंतजाम कर पाएगा ताकि करोड़ों युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके। इस मामले की गंभीरता का एक पहलू यह भी है कि सरकार के पास फिलहाल महज पैंतीस लाख युवाओं को हर साल किसी क्षेत्र में दक्ष बनाने वाले प्रशिक्षण देने का प्रबंध है। इसकी तुलना पड़ोसी चीन से करें, तो पता चलता है कि वहां सालाना नौ करोड़ युवाओं को हुनरमंद बनाने का इंतजाम सरकार की तरफ से किया गया है।

इस समस्या का दूसरा पहलू और भी गंभीर है। यह पहलू शिक्षण-प्रशिक्षण की गुणवत्ता से जुड़ा है। यह देखा जा रहा है कि अगर बच्चे और युवा किसी तरह नामी संस्थानों में दाखिला पा जाते हैं, तो भी इसकी गारंटी नहीं होती कि वहां से वे जो डिग्री-डिप्लोमा लेकर निकलेंगे, उसके आधार पर वे इतने काबिल हो सकेंगे कि अपने क्षेत्र में हर चुनौती से मुकाबला कर सकें। यह मामला स्कूल, कॉलेजों व प्रतिष्ठानों में दी जा रही शिक्षा की खराब गुणवत्ता से जुड़ा है। यही कारण है कि देश में सत्तावन फीसद युवा पढ़े-लिखे होने के बावजूद किसी ठीकठाक नौकरी के लिए तैयार नहीं पाए गए। जाहिर है, समस्या मौजूदा शिक्षा तंत्र की है जो वैसी शिक्षा नहीं दे पा रहा जो अच्छी नौकरी पाने या अपना कोई व्यवसाय खड़ा करने में उनकी मदद करे।

निश्चय ही ऐसे निष्कर्ष चिंताजनक हैं और सरकारों को इस दिशा में गंभीरता से सोचना चाहिए कि आखिर वे अपनी युवा आबादी को किस तरह की शिक्षा मुहैया करा रही हैं। शहरी और ग्रामीण शैक्षिक ढांचे में भीषण विरोधाभास हैं। कहीं शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है, तो कहीं हिंदी और क्षेत्रीय भाषा। ऐसा ही अंतर ग्रामीण और शहरी युवा की पढ़ाई-लिखाई का भी है। इस तरह के फर्क और अभावों को जितनी जल्दी हो सके, दूर करना बेहतर होगा।

परंपरा का आईना

निशा नाग

दुनिया मेरे आगे

काल को निरंतर प्रवाह की तरह देखना भारतीय परंपरा की विशेषता रही है। भारतीय मानस में काल एकरेखीय नहीं है, बल्कि चक्रीय है। यानी जो आज है, वह कल भी था और परसों भी होगा। यह आस्था रही है कि घटनाएं, व्यक्ति- सब यहां बार-बार अपने को दोहराते हैं। यानी जन्म-पुनर्जन्म के सिद्धांत ने व्यक्ति को मृत्यु के बाद पुनर्जीवन और दुख के पहाड़ टूट पड़ने पर पूर्वजन्म के कर्मों का फल कह कर संतोष कर लेने का सहारा दिया है। आम भारतीय जनमानस में बसे दो ग्रंथों 'रामायण' और 'महाभारत' में भी घटनाओं की तार्किकता पूर्वजन्म के प्रारब्ध और संचित कर्म व वर्तमान के कर्मों से निर्धारित होती है। यानी राजा दशरथ का राम के वनवास जाने पर प्राण त्याग देना उनसे श्रवण कुमार के अनजाने में हुए वध के कारण मिले श्राप का परिणाम था। 'महाभारत' की भी अनेक घटनाएं इसी तरह जन्म-पुनर्जन्म में किए गए कर्मों पर आधारित हैं। शायद इसीलिए भारतीय जनमानस ने पश्चिम की तरह इतिहास को संजोने का प्रयत्न नहीं किया।

आज जिस साक्ष्य के आधार पर इतिहास की इमारत खड़ी की जाती है, वे बर्तनों और औजारों के टूटे-फूटे जमीन में गड़े टुकड़े हैं। यह वह इतिहास है जो आम जन की बात नहीं करता, बल्कि कुछ विशेष जनों की बात करता है, जिन्हें नायक कहा जाता है। आम जन इस इतिहास में शायद कहीं भी नहीं। जन-इतिहास स्मृत ही होते हैं, जिन्हें पीढ़ियां अपने तरीके से वहन करती हैं। इतिहास अगर कहीं सुरक्षित रहा है तो वह या तो राज्याश्रय में या धर्माश्रय में या फिर लोकाश्रय में। भारत के संदर्भ में इतिहास की एक अन्य परंपरा रही है, जिसे स्मृत इतिहास कहा गया है। जहां किंवदंतियां, लोक कलाएं गाथाएं, मिथक और इतिहास अपने रूप और अंतर्वस्तु में इस तरह घुले-मिले हैं जैसे दूध और पानी। यह उन ऐतिहासिक साक्ष्यों से परे है जो इमारतों, बर्तनों के टुकड़ों, सिक्कों या फिर पांडुलिपियों में बसा रहता है।

हालांकि कुछ ऐसे साक्ष्य अवश्य मौजूद रहते हैं, जो आम और गुमनाम जनों की कथा को कह देता है। एक बार किसी पुरानी गढ़ी को देखते हुए उसके पूजा स्थल के बाहर लगे हुए हाथों के लाल निशान को दिखा कर गाइड ने बताया कि यह उन राजपूत रानियों के हाथ के निशान हैं जो सती हो गईं! उन्हें देखते हुए लगा कि कुछ निशान इतने छोटे थे जैसे दस और बारह वर्ष की बच्चियों के होते हैं और मन उन अज्ञात स्त्रियों के प्रति घोर करुणा से भर गया, जो अभी स्त्री बनी भी नहीं थीं। इसी तरह, जोधपुर में घर के समीप तापी बावड़ी को देखते हुए मुझे बताया गया कि अभी जब इसकी सफाई हुई तो काफी मात्रा में इसमें से सोने-चांदी के गहने निकले, जिसे सरकार ने अपनी पास रख लिया है। मेरा प्रश्न था कि क्या यहां गहने छिपाए गए थे, तो उत्तर मिला- 'यह उन महिलाओं के थे, जिन्होंने पारिवारिक क्लेश, निस्सतांन होने या अन्य किसी दुख से यहां डूब कर आत्महत्या कर ली थी'। उन स्त्रियों का कोई इतिहास या स्मृति चिह्न नहीं है। केवल स्त्री के दुख की शाश्वत गाथा यहां भी मौजूद है।

आम जन का इतिहास कहीं और भी सुरक्षित रहा है। अभी अपने आत्मीय के असमय काल कलवित होने पर हरिद्वार जाना पड़ा। यह पहले मालूम था कि यहां पर परिवारों के परंपरागत पंडे हैं जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी कर्मकांड करवाते रहे हैं। उनके पास ढेरों पुराने बही-खाते थे। उन सबमें स्थान विशेष के अनेक खानदानों का इतिहास दर्ज था कि कौन कब काल-कवलित हुआ और उसके फूल लेकर कौन-कौन आया! उनके अनुसार, उनके पास तीन सौ सालों का इतिहास दर्ज है। हरिद्वार के अलावा भी भारत में अन्य स्थानों पर भी यही परंपरा रही है।

सभी जगह बही-खाते और वहां आकर श्राद्ध कर्म करवाने वालों का इतिहास इसी तरह दस्तावेजों में दर्ज है। यह जान कर हैरानी भी होती है कि आज से दो-तीन सौ वर्ष पूर्व, जब यातायात के साधन मौजूद नहीं थे, लोग कैसे दूरदराज से वहां तक पहुंचते थे! बैलगाड़ी पर महीनों की कठिन यात्राएं ही तब एकमात्र उपाय रहा होगा। मगर तब भी आस्था उन्हें वहां तक पहुंचाती थी। पॉल वाइस के अनुसार अपने को अतीत से जोड़ने में आनंदानुभूति होती है, मनुष्य अपने स्रोत की चेतना से अपने को आश्वस्त कर लेता है कि वह अकेला है। यह मनुष्य का स्वभाव है कि वह किसी चीज को किसी परिप्रेक्ष्य में रख कर ही पहचान सकता है। यह शायद काल के असंख्य प्रवाह में एक बिंदु के समान स्थित मानव के अस्तित्व को समझने का प्रयत्न हो।

यह एक सच्चाई है कि आज की चूहादौड़ में फंसी दुनिया में किसे फुर्सत है बीते कल की फिक्र करने की! पर हम दौड़ में पल भर भी थम कर सोचें कि आज तो कल की नींव पर ही खड़ा है और आने वाला कल लगातार आज बनता चला जा रहा है तो अतीत वर्तमान और भविष्य- अनिवार्य रूप से अविभाज्य लगने लगेगें और यह भी की इतिहास परंपरा का ही एक हिस्सा है।

प्रकृति से खिलवाड़

दुनिया आज एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां जिंदगी का पर्याय मौत हो गया है। धरती के एक भू-भाग में बाढ़ का कहर है, तो दूसरे में सूखे की मार। धरती की इस दुर्गति की जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी है, यह एक यक्ष प्रश्न है। हम दुनिया को अपनी आंखों के सामने बद से बदतर होते देख रहे हैं और हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम इस पर मौन हैं। हम विकास की सीढ़ियां चढ़ते हुए जंगलों को काट कर रहे हैं और खुद की पीठ थपथपा रहे हैं। हमारे पास आज इतना भी वक्त नहीं है कि हम कुछ पल निकाल कर यह सोचें कि जिस दुनिया में सांस लेने के लिए शुद्ध हवा ही नहीं होगी, वहां मेट्रो, मॉल और बुलेट ट्रेन के होने का क्या मतलब रह जाएगा। पानी और हवा जैसी बुनियादी चीजों के अभाव में हमारा विकास धरा का धरा रह जाएगा। आज आप अपने आसपास नजर डालें तो यह पाएंगे कि सबसे अधिक बीमारी से कोई जूझ रहा है तो वह देश का युवा है। युवा अवसाद का शिकार है, अस्थमा, उच्च रक्तचाप का शिकार है, उसका शरीर जर्जर है और हम युवा भारत पर अपनी छाती चौड़ी करके घूम रहे हैं। हमें यह चिंतन करना चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ी को अच्छी दुनिया में नहीं, अपितु खोखले विकास में जन्म दे रहे हैं। इस हकीकत पर अगर हम शर्मिंदा हों तो यह हमारी विनम्रता नहीं, अपितु ईमानदारी होगी।

● *मुकुल सिंह चौहान, जामिया, दिल्ली*

कामयाबी की उड़ान

भारतीय वायु सेना की जांबाजी के किस्से हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर देते हैं। दुनिया की चौथी बड़ी सैन्य शक्ति वाली भारतीय वायु सेना की जाबांजी के कई किस्से मशूहर हैं। 1932 में गठित भारतीय वायु सेना में साल दर साल इसकी बेहतरी का प्रयास किया गया है। किसी भी सरकार का पहला मकसद होता है कि आकाश में दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाली भारतीय वायु सेना को सवश्रेष्ठ बनाया जाए। पहले कमांडर इन चीफ एयर मार्शल सर थॉमस वाकर एमहिस्ट ने भारतीय वायु सेना को एक ऐसी सेवा के रूप में स्थापित किया जिसकी मदद से देश को सुरक्षित रखा जा सके। अपने शुरुआती दौर में भारतीय थल सेना का कमांडर इन चीफ ही भारतीय वायु सेना पर नियंत्रण रखता था।

तकनीकी मामले में कुछ देश हमारी वायुसेना से आगे हो सकते हैं, लेकिन अपने संसाधनों के सटीक प्रयोग और बुद्धिमता के कारण हमारी वायुसेना से दुश्मन देश हमेशा थर्राते हैं। करीब डेढ़ हजार विमानों से लैस भारतीय वायु सेना के बेड़े में कुछ एक ऐसे लड़ाकू विमान हैं जिन पर पूरे देश को नाज है। वायु सेना के बेड़े में चालीस सुखोई विमान शामिल हैं। जंग के दौरान हेलिकॉप्टरों की भूमिका भी काफी अहम होती है जिसे कई तरीके से काम में लिया जाता है। खास तौर पर युद्ध के स्थान पर लड़ रहे सेना के जवानों के लिए जरूरी सामान खाने-पीने की चीजें लाने और ले जाने के साथ-साथ दुर्गम स्थानों पर छिड़ी जंग में सैनिकों को ले जाने में ये हेलिकॉप्टर अहम भूमिका निभाते हैं।

● *अमन सिंह, बरेली*

मानसून की वापसी

आधिकारिक रूप से दक्षिण-पश्चिम मानसून को अब तक भारत से लौट जाना चाहिए था, लेकिन देश के विभिन्न भागों में अभी भी वर्षा का दौर जारी है। इस वर्ष जून को छोड़ दें तो अन्य मानसूनी महीनों जुलाई, अगस्त और सितंबर में सामान्य से क्रमशः 104.6, 115.4 और 152.3 फीसद अधिक वर्षा हुई है। सितंबर में हुई वर्षा सन 1917 के बाद सर्वाधिक है जब सामान्य से 165 फीसद अधिक वर्षा हुई थी, जो ला-निना से प्रभावित वर्ष था। इस वर्ष मानसून का आगमन भी लगभग एक हफ्ते देरी से हुआ था।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलुरु के वैज्ञानिक जे श्रीनिवासन का मानना है कि आइओडी, जिसे इंडियन ला-निना भी कहते हैं, के बने रहने की वजह से मानसून की वापसी में देरी हो रही है। मौसम विभाग ने दस अक्तूबर के बाद मानसून के लौटने की उम्मीद जताई है। इस दौरान अगर पश्चिमी राजस्थान में लगातार पांच दिन तक वर्षा नहीं होती तो मानसून लौटने की आधिकारिक घोषणा हो सकती है। पिछले साल भी मानसून की वापसी अक्तूबर के दूसरे सप्ताह से शुरू हुई थी।

● *शिवशंकर यादव, इलाहाबाद विवि*

हरित पटाखे

केंद्र ने दीपावली पर प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्यावरण अनुकूल हरित पटाखे की शुरुआत कर सराहनीय कदम उठाया है। विज्ञान, तकनीक, स्वास्थ्य एवं भूविज्ञान मंत्री ने हरित पटाखों से बढ़ते ध्वनि और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने का दावा भी किया है। यह कदम कितना सार्थक होगा, यह आने वाले समय में ही पता चलेगा। शहरों में जानलेवा प्रदूषित वातावरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट कई बार चिंता जाहिर कर चुका है। कहा जा रहा है कि हरित पटाखे इस प्रदूषित वातावरण को तीस फीसद तक कम कर सकतें हैं, क्योंकि इनमें प्रदूषण फैलाने वाले तत्व बोरियम नाइट्रेट की मात्रा अत्यंत कम होती है। अगर सरकार के इस कदम को जनता का विश्वास और सहयोग मिलता है तो निस्संदेह देश में प्रदूषण पर कुछ सीमा तक रोक लगाई जा सकती है।

● *बिजेंद्र कुमार, दिल्ली विश्वविद्यालय*

कलयुग का रावण जलाएं

त्रेतायुग में तो एक रावण था, लेकिन कलयुग में तो हर जगह रावण है। त्रेतायुग के रावण से ज्यादा तो आज के रावण पापी नजर आते हैं। कलयुग के रावण के दस से भी ज्यादा सिर विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीति की व्याधियों के रूप में मौजूद हैं, जिनमें स्वार्थ, बेईमानी, हेराफेरी, अनैतिकता, भ्रष्टाचार, शोषण, नशा, धर्म-जाति पर हिंसा जैसी बुराइयां फैली हैं। दशहरे के दिन लोग रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ और अन्य राक्षसों के पुतलों को आग लगाकर खुशी मनाते हैं। पर इन पुतलों के साथ सभी को अपनी बुराइयों को भी जलाना चाहिए। भविष्य में कभी भी गलत न करन की शपथ लेनी चाहिए। आज समाज में बहुत से ऐसे लोग है जो अपनी किसी शक्ति चाहे वह धन की हो, शरीर की हो या पद की, उसके अहंकार में आकर दूसरों लोगों की मजबूरियों का फायदा उठा कर उन्हें परेशान करते हैं। अहंकारी लोगों को कोई भी अच्छा नहीं कहता है। इसलिए दशहरे पर यह संकल्प लेना चाहिए कि हम कभी भी किसी बात का अहंकार न करें।

● *राजेश कुमार चौहान, जलंधर*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com